जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय

आठवां द्विवार्षिक सम्मेलन

24–26 अक्तूबर, 2010, बड़वानी मध्य प्रदेश

आमंत्रण – सभी आमंत्रित हैं!

शांति, न्याय एवं लोकतंत्र की ओर .....

मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के बड़वानी में आयोजित **जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय** (एनएपीएम) के आठवें द्विवार्षिक सम्मेलन में आपको आमंत्रित करते हुए खुशी हो रही है। इस सम्मेलन का मेजबान नर्मदा बचाओ आंदोलन जो कि एनएपीएम के संस्थापक संगठनों में से एक है और वह अपने संघर्ष के 25वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। सन 1992 से शुरू हुई एनएपीएम की यात्रा ने 1996 में एक आकार लिया और आज एक अहम दौर में प्रवेश कर चुका है।

हमारी यात्रा तब शुरू हुई जब उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने पैर पसारना शुरू किया, बाबरी मस्जिद ढहाने की आड़ में हिंदूवादी ताकतों ने सिर उठाना शुरू किया और उस दौर में यह घोषणा कि गई कि कोई विकल्प मौजूद नहीं है। **तब से अब तक हमने हमने एक लम्बी यात्रा पूरी की है और विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.), विश्व बैंक, एनरॉन, बड़े बांध, ग्रामीण एवं शहरी बेदखली व विस्थापन, महिलाओं, आदिवासियों के प्रति अत्याचार और दलित सांप्रदायिकता के खिलाफ कई अन्य आंदोलनों, स्वैच्छिक संगठनों, संघों एवं मंचों, संवेदनशील बुद्धिजीवियों, कलाकारों, छात्रों एवं अन्य के साथ कई महत्वपूर्ण संघर्षों का आयोजन किया है**। सन 2003 में, हमने वैकल्पिक दुनिया के आदर्श को वास्तविकता में बदलने के लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन विकसित करने, लोगों के सामूहिक राजनैतिक ताकत के तौर पर मौजूदा गरीब विरोधी एवं विकास विरोधी विकास प्रतिमान को बढ़ावा देने वाली राजनैतिक व्यवस्था को बदलने के उद्देश्य से एक देशव्यापी अभियान ''**देश बचाओ–देश बनाओ**'' शुरू किया। सन 2007 में, कई अन्य समन्वयों, मचों एवं संघों को समाहित करते हुए ***संघर्ष*** की प्रक्रिया शुरू की गई, जो कि एक बेहतर दुनिया हासिल करने की दिशा में एक अन्य कदम था।

एक दशक बाद हम नर्मदा घाटी में मिले, **एक बार फिर हम ऐसे समय में मिल रहे हैं, जो कि सबसे अच्छे और सबसे बुरे समयों में से है**। नव उदारवाद की जो प्रक्रिया तब शुरू हुई थी उसने अब अपना असल रंग दिखाना शुरू कर दिया है, सार्वजनिक एवं निजी कॉरपोरेशनों दोनों ही न सिर्फ संसाधनों को हड़प रहे हैं, बल्कि बाजार एवं संबंधित उपायों से राजनैतिक अवसर एवं सत्ता पर कब्जा कर रहे हैं। राष्ट्रीय से लेकर अंतरराष्ट्रीय निवेशकों ने समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के हर आयाम का ''निजीकरण'' कर दिया है। **आज बदलाव कल्पना के प्रति एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग एवं ऊर्जा संकट और भी ज्यादा जाहिर हो रहा है**। राज्य कल्याण एवं परोपकारी का चोला उतारकर मात्र बिचौलिया की भूमिका निभा रहा है, राजनैतिक वर्ग एवं ज्यादा मुखर मध्यम वर्ग बाजार की विचारधारा एवं अर्थव्यवस्था व विकास के नव–उदारवादी मॉडलों के प्रति बिक चुके हैं। हम श्रम के अनौपचारीकरण के गवाह हैं जिसके परिणामस्वरूप आज 96 फीसदी कामगार असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत हैं और अमीरों व गरीबों के बीच दूरी बढ़ रही है। इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा की समाप्ति, कृषि पर हमला सहित खाद्यान्नों की कीमत में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है।

राजनैतिक वर्ग लोगों के मुद्दे को शायद ही कभी हल करते हैं बल्कि उन्हें अधिकतर वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते हैं। **सार्वजनिक अवसर, सार्वजनिक हित, सार्वजनिक पटल एवं प्राथमिकताएं इतने कम हो रहे हैं कि वे बुनियादी जरूरतों की पूर्ति भी नहीं हो पा रही है जो कि न सिर्फ वर्तमान को बल्कि भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं**। जबकि, हम यह भी नहीं भूल सकते कि सरकार द्वारा थोपे जाने वाले ''आतंक के खिलाफ युद्ध'', सैन्यीकरण एवं हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति से अहिंसक जन संघर्षों के लिए मुश्किलें बढ़ रही है, बल्कि साथ ही उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण भी बना रही हैं।

ये समय उतने निराशावादी नहीं हैं, हमारे सामूहिक प्रयासों से न सिर्फ सूचना का अधिकार कानून, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम आदि प्रगतिशील कानून लागू हुए हैं, बल्कि ऐसी परिस्थिति भी उत्पन्न हुई जहां लोगों ने जल, जंगल, जमीन एवं खनिज आदि के लूट के हर प्रयास को जमीनी स्तर पर चुनौती दी। हम सिंगुर, नंदीग्राम, नियमगिरि, सोमपेटा, कारला, चेंगारा एवं संघर्ष के ऐसे कई जगहों में जीत के बीच खड़े हैं। न्याय और समानता का सवाल पहले से कही ज्यादा सामने है एवं जनता, सरकार एवं कॉरपोरेशनों के बीच '***प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार एवं नियंत्रण***' आज प्रतिवाद का केन्द्र बिन्दु बन गया है। आज एनएपीएम सिर्फ समन्वय नहीं है और हमारे दायरे से बाहर भी बड़ी बिरादरी है जो कि विकल्पों के माध्यम से संघर्ष और पुनर्निर्माण में लगे हुए हैं, और सरकार एवं कॉरपोरेटों दोनों के भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों एवं कठोरता के समक्ष निगमीकरण एवं वैश्वीकरण को चुनौती देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने हमेशा उनके बीच अवसर तैयार करने एवं चर्चा और देश में मौजूद संघर्षों व विचारधाराओं की विविधता को पर्याप्त अवसर प्रदान करने की की कोशिश की है।

एक सकारात्मक पक्ष के तौर पर इसे हमारी सामूहिक जीत समझा जा सकता है कि आज सामाजिक कार्यकर्ता एवं मानव अधिकार कार्यकर्ता सरकार एवं उनके द्वारा निर्मित डिजाइनों के लिए इतना अधिक खतरा बन गये हैं कि उन्हें झूठे तौर पर 'माओवादी' या 'आतंकवादी' कहा जा रहा है। सांप्रदायिकता का जहर विभिन्न तरीके से समाज व शासन के रगो में फैल चुका है और उनसे लड़ने के लिए अलग–अलग समझ एवं रणनीति की जरूरत है। **सरकार द्वारा हम पर थोपी गई सशस्त्र युद्ध एवं गैर–सरकारी एवं निजी सुरक्षा बलों द्वारा प्रतिहिंसा से ऐसी परिस्थिति पैदा हो रही है जिससे इस विकास प्रक्रिया में हाशिये में खड़े लाखो लोगों का जीवन व आजीविका को खतरा उत्पन्न हो रहा है**। सांप्रदायिकता, निगमीकरण एवं अस्पष्ट जातिवाद एवं पितृसत्ता के तत्व एक साथ मिलकर न सिर्फ लोकतांत्रिक समाज के ढांचे के प्रति खतरा उत्पन्न कर रहे हैं बल्कि मौजूदा पारंपरिक लोकतंत्र के विरूद्ध लोगों के वास्तविक लोकतंत्र के सामूहिक प्रयास के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं।

आगामी दशक में अधिकार हासिल करने एवं जल, जंगल, जमीन एवं खनिज पर नियंत्रण के लिए जबरदस्त संघर्ष होने की संभावना है और इस तरह दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, अल्पसंख्यको, मजदूरों, भूमिहीन किसानों एवं विकास में पीछे छूट गये अन्य लोगों के लिए न्याय सुनिश्चित करना काफी कठिन होगा। हम सरकार के ''सर्वोपरि के सिद्धांत'' को चुनौती देते हैं और सत्ता को चुनौती देते हैं क्योंकि वह सिर्फ कॉरपोरेशनों की मध्यस्थ बन चुकी है और उनके पूंजीवादी हितों की रक्षा करने के लिए सेना का इस्तेमाल करती है। चाहे भूमि अधिग्रहण हो, विस्थापन या पुनर्वास के मुद्दे हो, आज ज्यादातर का राजनीतिकरण एवं ध्रुवीकरण हो रहा है, तो जरूरत इस बात की है कि आंदोलनों एवं समर्थकों के बीच शांति

एवं लोकतंत्र के माध्यम से समानता एवं न्याय सुनिश्चित करने के लिए विकास नियोजन पर ... और इस तरह एक समन्वय के लिए सहमति बने!

ऐसे चुनौतीपूर्ण समय में एनएपीएम आपको आठवें द्विवार्षिक सम्मेलन में विभिन्न जन आंदोलनों एवं संगठनों को एक मजबूत समन्वय के निर्माण के लिए आमंत्रित करता है। सम्मेलन का उद्देश्य ऐसा मंच उपलब्ध कराना है जहां कि विभिन्न मुद्दों, आंदोलनों एवं नागरिक समाज के प्रतिक्रियाओं पर सामूहिक चर्चा किया जा सके और जनशक्ति एवं जन राजनीति के साथ अभिनव रणनीतियों सहित एक नयी राजनैतिक शक्ति शुरूआत करने की ओर काम किया जा सके। इसके लिए आपकी उपस्थिति एवं योगदान काफी महत्वपूर्ण है। कृपया सम्मेलन में अवश्य शामिल हों!

संभावित कार्यक्रम इस प्रकार हैं, विस्तृत कार्यक्रम बाद में प्रेषित किया जाएगाः
24 अक्तूबरः उदघाटन समारोह, विषयपरक सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम
25 अक्तूबर : विषयपरक सत्र
26 अक्तूबर : समन्वयकों के दल का चुनाव, प्रस्ताव

कार्यक्रम स्थल एवं सम्पर्क व्यक्ति के बारे में मार्गदर्शन निम्नलिखित है। कृपया किसी भी अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए निःसंकोच सम्पर्क करें। हमेशा की तरह हमारे साथ आकर ज्यादा समय बिताने, हमारे साथ काम करने, हमारे साथ वालंटियर बनने, हमें संसाधनो का सहयोग करने, या हमारे साथ यात्रा में शामिल होने के लिए आपका स्वागत है.....।

समारोह की शुरूआत नर्मदा घाटी में संघर्ष के 25 साल के कार्यक्रम के साथ होगा। उदघाटन कार्यक्रम महाराष्ट्र के धड़गांव में 22 अक्तूबर को एवं समापन मध्य प्रदेश के बड़वानी में 23 अक्तूबर 2010 होगा। इसके लिए अलग से आमंत्रण प्रेषित किया गया है। कृपया विस्तृत जानकारी के लिए लिखें:
nba.badwani@gmail.com; 25yearsofnba@gmail.com; 07290—222464 / 09423944390 / 09423965152 / 09420375730 / 02595.220620

कृपया अपने आगमन के बारे में हमें सूचित करें ताकि हम पर्याप्त व्यवसथा कर सकें...। आप हमें फोन या ईमेल से सम्पर्क कर सकते हैं:

napmindia@napm-india.org | madhuresh@napm-india.org | www.napm-india.org

सादर,

एनएपीएम समन्वयक दल

दिल्ली कार्यालयः

द्वाराः 6/6, जंगपुरा बी, नयी दिल्ली, फोन– *011 – 2437 4535 / 9818905316/ 9868200316*

राष्ट्रीय कार्यालयः

कमरा संख्या 29–30, प्रथम तल, 'ए' विंग, हाजी हबीब बिल्डिंग, नईगांव क्रॉस रोड, दादर (पूर्व), मुम्बई – 400014, फोनः 022–24150529/ *9969363065*

बड़वानी सम्पर्कः

नर्मदा बचाओ आंदोलन, 62 महात्मा गांधी मार्ग, बड़वानी, मध्य प्रदेश – 451551

फोन : 07290–222464, फैक्स : 07290–222549;nba.badwani@gmail.com

अन्य सम्पर्क :

असम, अखिल गोगोई/अरूपज्योति सैकिया :9435054140 / 9435557483

आंध्र प्रदेश, रामकृष्ण राजू : 9866887299

बिहार, आशीष रंजन : 9973363664

छत्तीसगढ़, गौतम बंदोपाध्याय : 9826171304

दिल्ली, राजेन्द्र रवि / मधुरेश : 9868200316 / 9818905316

गुजरात, आनंद मझगांवगर /स्वाति देसाई : 02640 220629 / 9429556163

कर्नाटक, सिस्टर सेलिया : 9945716052

केरल, लियो जोस/हुसैन मास्टर : 9446000701/ 9445375379

मध्य प्रदेश, श्रीकांत : 07290.222464 / 9179148973

महाराष्ट्र, सुनीति आर/सिम्प्रीत सिंह : 09423571784 / 9969363065

उड़ीसा, प्रफुल्ल सामंत्रा : 9437259005

तमिलनाडु, गैबरियेल डेइटरिच : 09442511292

उत्तर प्रदेश, संदीप पांडेय/ अरूंधति धुरू : 05222347365 / 9415022772

पश्चिम बंगाल, देबजीत दत्ता : 09433830031